Online at: www.multiarticlesjournal.com OPEN ACCESS ISSN No. 2583-7397

International Journal of Contemporary Research in Multidisciplinary; 2023: 2(1): 86-88

वैश्वीकरण, श्रम बाजार और अल्पसंख्यक महिलाओं की नई पहचान

डॉ० शारदा कुमारी
सहायक प्राध्यापक, वाई. बी.एन. यूनिवर्सिटी, रांची, झारखण्ड, झारखंड भारत

Corresponding Author: * डॉ० शारदा कुमारी

सारांश

वैश्वीकरण आधुनिक विश्व की सबसे प्रभावशाली सामाजिक-आर्थिक प्रक्रिया है, जिसने मानव जीवन के लगभग सभी पक्षों को प्रभावित किया है। यह केवल आर्थिक उदारीकरण या बाजार विस्तार की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक मूल्यों, राजनीतिक व्यवस्थाओं और व्यक्तिगत पहचानों को पुनर्गठित करने वाली एक व्यापक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। वैश्वीकरण के कारण पूंजी, तकनीक, सूचना और श्रम का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीव्र प्रवाह हुआ है, जिसने राष्ट्रीय सीमाओं के महत्व को आंशिक रूप से कम किया है। इसके परिणामस्वरूप श्रम बाजार का स्वरूप बदला है और रोजगार की प्रकृति में गहरे परिवर्तन आए हैं।

इन परिवर्तनों का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ा है, किंतु यह प्रभाव समान नहीं रहा। विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव बहुस्तरीय, जटिल और द्वंद्वात्मक रहा है। ये महिलाएँ पहले से ही लैंगिक असमानता, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक वंचना का सामना करती रही हैं। वैश्वीकरण और उससे उत्पन्न नए श्रम बाजार ने एक ओर उन्हें नए अवसर प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी ओर असुरक्षा, शोषण और असमानता की नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। इस लेख में वैश्वीकरण, श्रम बाजार और अल्पसंख्यक महिलाओं की नई पहचान के बीच संबंधों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया है।

Publication Information

Received Date: 05-01-2023
Accepted Date: 27-01-2023
Publication Date: 30-01-2023

How to cite this article:

डॉ० शारदा कुमारी, वैश्वीकरण, श्रम बाजार और अल्पसंख्यक महिलाओं की नई पहचान. Int J Contemp Res Multidiscip. 2023;2(1):86-88.

मुख्य शब्द: वैश्वीकरण, श्रम बाजार, अल्पसंख्यक महिलाएँ, नई पहचान, आर्थिक सशक्तिकरण, असंगठित क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, रोजगार अवसर, लैंगिक समानता, सामाजिक परिवर्तन, असमानता, असुरक्षित रोजगार, शोषण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, सांस्कृतिक बाधाएँ, आत्मनिर्भरता, नीतिगत हस्तक्षेप ।

परिचय

इक्कीसवीं सदी में वैश्वीकरण ने विश्व की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं में गहरे और दूरगामी परिवर्तन किए हैं। उत्पादन, व्यापार, पूँजी और सूचना के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह ने जहाँ एक ओर आर्थिक अवसरों का विस्तार किया है, वहीं दूसरी ओर श्रम बाजार की प्रकृति को भी मूलतः बदल दिया है। इस परिवर्तित श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से बढ़ी है, परंतु अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया अवसरों के साथ-साथ नई चुनौतियाँ भी लेकर आई है। वैश्वीकरण के संदर्भ में श्रम बाजार केवल रोजगार का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि पहचान, अस्मिता और सामाजिक स्थिति के पुनर्निर्माण का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है।वैश्वीकरण के प्रभाव से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार के स्वरूप बदले हैं। सेवा क्षेत्र, घरेलू श्रम, निर्यात-उन्मुख उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा असंगठित क्षेत्र में अल्पसंख्यक महिलाओं की उपस्थिति उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। परंतु यह भागीदारी प्रायः असुरक्षित रोजगार, कम वेतन, अस्थायी अनुबंध, सामाजिक सुरक्षा की कमी और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसी समस्याओं से जुड़ी हुई है। धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के कारण अल्पसंख्यक महिलाओं को बहुस्तरीय वंचना का सामना करना पड़ता है, जहाँ लैंगिक असमानता के साथ-साथ समुदाय-आधारित भेदभाव भी उनके श्रम अनुभव को प्रभावित करता है।

इस बदलते परिदृश्य में अल्पसंख्यक महिलाओं की पहचान केवल पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं तक सीमित नहीं रह गई है। वैश्वीकरण और श्रम बाजार में उनकी बढ़ती भागीदारी ने उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सक्रिय, आत्मनिर्भर और निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बनाया है। रोजगार के माध्यम से शिक्षा, कौशल

विकास, सामाजिक गतिशीलता और आत्मसम्मान में वृद्धि ने एक "नई पहचान" को जन्म दिया है, जिसमें वे केवल श्रमिक नहीं, बल्कि परिवार और समाज में परिवर्तन की वाहक के रूप में उभर रही हैं। साथ ही, यह नई पहचान संघर्ष और प्रतिरोध की भी प्रतीक है, क्योंकि वे असमानताओं, शोषण और सांस्कृतिक दबावों के विरुद्ध अपने अधिकारों की माँग कर रही हैं।

इस प्रकार, वैश्वीकरण, श्रम बाजार और अल्पसंख्यक महिलाओं की नई पहचान का अध्ययन केवल आर्थिक विश्लेषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समावेशी विकास की व्यापक बहस से भी जुड़ा हुआ है। यह परिचय इस जटिल अंतर्संबंध को समझने की भूमिका तैयार करता है, जहाँ अवसर और चुनौतियाँ दोनों मिलकर अल्पसंख्यक महिलाओं की बदलती अस्मिता को आकार दे रही हैं।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विकास अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज है। औद्योगिक क्रांति, औपनिवेशिक विस्तार और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास ने वैश्वीकरण की आधारभूमि तैयार की। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेष रूप से शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्वीकरण ने तीव्र गति पकड़ी। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और नवउदारवादी नीतियों ने वैश्वीकरण को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया।भारत जैसे विकासशील देशों में वैश्वीकरण का प्रभाव *1991* के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियाँ लागू की गईं। इन नीतियों के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व बाजार से जुड़ी और श्रम बाजार में संरचनात्मक परिवर्तन आए। परंपरागत कृषि और औद्योगिक रोजगार की तुलना में सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिसने महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए।

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप श्रम बाजार का स्वरूप मौलिक रूप से बदल गया है। स्थायी, संगठित और सुरक्षित रोजगार की जगह अस्थायी, ठेका आधारित और लचीले रोजगार संबंधों ने ले ली है। गिग इकॉनॉमी, आउटसोर्सिंग, घरेलू सेवा, खुदरा व्यापार, कॉल सेंटर और आईटी-सक्षम सेवाएँ वैश्वीकृत श्रम बाजार की प्रमुख विशेषताएँ हैं।महिलाओं के लिए यह परिवर्तन दोहरे अर्थों में महत्वपूर्ण है। एक ओर इन क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जिससे उन्हें घरेलू सीमाओं से बाहर निकलने का अवसर मिला है। दूसरी ओर इन क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को कम वेतन, लंबे कार्य-घंटे, सामाजिक सुरक्षा के अभाव और असुरक्षित कार्य-परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि वे लैंगिक असमानता के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक भेदभाव का भी सामना करती हैं।

अल्पसंख्यक महिलाएँ समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं जो बहुआयामी वंचना से गुजरता है। महिला होने के कारण लैंगिक भेदभाव, अल्पसंख्यक होने के कारण सामाजिक-धार्मिक हाशियाकरण और कई मामलों में गरीबी—ये सभी कारक उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। परंपरागत समाजों में इन महिलाओं की भूमिका घरेलू कार्यों और पारिवारिक जिम्मेदारियों तक सीमित रही है। शिक्षा की कमी, सामाजिक रूढ़ियाँ और सामुदायिक नियंत्रण ने उनकी सार्वजनिक भागीदारी को सीमित किया है। किंतु वैश्वीकरण ने इन पारंपरिक संरचनाओं को आंशिक रूप से चुनौती दी है। रोजगार की नई संभावनाओं ने अल्पसंख्यक महिलाओं को श्रम बाजार में प्रवेश का अवसर दिया है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के संकेत मिलते हैं।

वैश्वीकरण के साथ-साथ अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए रोजगार के नए क्षेत्र विकसित हुए हैं। वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प, घरेलू सेवा, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वयं सहायता समूह और लघु उद्यमिता—ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अल्पसंख्यक महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र ने महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक अवसर प्रदान किए हैं।

आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी ने महिलाओं को आय अर्जन का साधन दिया है, जिससे उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है। आय के माध्यम से महिलाओं का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ा है। अब वे केवल पारिवारिक आश्रित न रहकर आर्थिक योगदानकर्ता के रूप में पहचानी जाने लगी हैं। यह परिवर्तन उनकी सामाजिक पहचान में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है।

वैश्वीकरण और श्रम बाजार के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं की एक नई पहचान उभर रही है। यह पहचान केवल धार्मिक या सामुदायिक पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि एक श्रमिक, पेशेवर और नागरिक की पहचान भी इसमें शामिल है। कार्यस्थल पर सहभागिता ने महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में दृश्यता प्रदान की है।नई पहचान का यह निर्माण सरल नहीं है। यह प्रक्रिया संघर्ष, अनुकूलन और प्रतिरोध से होकर गुजरती है। महिलाएँ पारंपरिक भूमिकाओं और आधुनिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही हैं। इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में उनकी पहचान गतिशील और बहुआयामी बनती जा रही है। यद्यपि वैश्वीकरण ने अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी स्पष्ट हैं। श्रम बाजार में अल्पसंख्यक महिलाओं को अक्सर कम वेतन, अस्थायी रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के अभाव का सामना करना पड़ता है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए श्रम कानूनों का संरक्षण सीमित होता है।इसके अतिरिक्त, धार्मिक पहचान और लैंगिक भेदभाव के कारण कार्यस्थल पर भेदभाव और उत्पीड़न की समस्याएँ भी सामने आती हैं। कई बार अल्पसंख्यक महिलाओं को उनकी पहचान के आधार पर कमतर आँका जाता है। इस प्रकार वैश्वीकरण के लाभ समान रूप से वितरित नहीं हो पाते।शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वैश्वीकरण का प्रभाव अलग-अलग रूप में दिखाई देता है। शहरी क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र और औद्योगिक गतिविधियों के कारण महिलाओं के लिए अधिक अवसर उपलब्ध हैं। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सीमित हैं और महिलाएँ मुख्यतः कृषि या असंगठित श्रम पर निर्भर रहती हैं।

अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए यह अंतर और भी स्पष्ट है। शहरी क्षेत्रों में वे अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता और अवसर प्राप्त करती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक सामाजिक नियंत्रण अधिक प्रभावी रहता है। यह अंतर उनकी पहचान और सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करता है।अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा और कौशल

विकास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैश्वीकृत श्रम बाजार में वही महिलाएँ बेहतर अवसर प्राप्त कर पाती हैं जिनके पास शिक्षा और तकनीकी कौशल होता है। शिक्षा न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाती है, बल्कि महिलाओं में अधिकार-बोध और सामाजिक जागरूकता भी विकसित करती है।कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक शिक्षा अल्पसंख्यक महिलाओं को श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धी बना सकती है। इससे उनकी नई पहचान को स्थायित्व और सशक्त आधार मिल सकता है।वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य की भूमिका समाप्त नहीं हुई है, बल्कि उसका स्वरूप बदला है। सरकार और नीति-निर्माताओं की जिम्मेदारी है कि वे अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए समावेशी और संवेदनशील नीतियाँ बनाएँ। रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा, समान वेतन और सुरक्षित कार्य-परिस्थितियाँ सुनिश्चित करना आवश्यक है।इसके साथ ही गैर-सरकारी संगठन, नागरिक समाज और सामुदायिक संस्थाएँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। सामूहिक प्रयासों से ही वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाया और नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष

वैश्वीकरण, श्रम बाजार और अल्पसंख्यक महिलाओं की नई पहचान के बीच गहरा और जटिल संबंध है। वैश्वीकरण ने एक ओर अल्पसंख्यक महिलाओं को आर्थिक अवसर, आत्मनिर्भरता और सामाजिक दृश्यता प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर असमानता, असुरक्षा और शोषण की नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न की हैं। उनकी नई पहचान संघर्ष, परिवर्तन और संभावनाओं के बीच निर्मित हो रही है।

आवश्यक है कि वैश्वीकरण को केवल बाजार-केन्द्रित प्रक्रिया के रूप में न देखकर मानव-केन्द्रित दृष्टिकोण से समझा जाए। शिक्षा, कौशल विकास, सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता के माध्यम से ही अल्पसंख्यक महिलाओं को श्रम बाजार में सम्मानजनक स्थान और सशक्त पहचान मिल सकती है। यदि वैश्वीकरण को समावेशी और संवेदनशील बनाया जाए, तो यह अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का माध्यम बन सकता है, न कि केवल एक नई चुनौती।

संदर्भ सूची

1. अप्पादुरई ए. आधुनिकता का विस्तार: वैश्वीकरण के सांस्कृतिक आयाम. मिनियापोलिस: यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा प्रेस; 1996.
2. बेक यू. वैश्वीकरण क्या है? कैम्ब्रिज: पॉलिटी प्रेस; 2000.
3. देसाई एन, ठक्कर यू. भारतीय समाज में महिलाएँ. नई दिल्ली: राष्ट्रीय पुस्तक न्यास; 2001.
4. भारत सरकार. सच्चर समिति की रिपोर्ट: भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति. नई दिल्ली: अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय; 2006.
5. झारखंड सरकार. झारखंड राज्य मानव विकास रिपोर्ट. राँची: योजना एवं विकास विभाग; 2018.
6. कबीर एन. चयन की शक्ति: लंदन और ढाका में श्रम बाजार में महिलाओं के निर्णय. लंदन: वर्सो प्रकाशन; 2000.
7. सेन ए. विकास के रूप में स्वतंत्रता. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 1999.
8. स्टैंडिंग जी. प्रिकैरियट: नया खतरनाक वर्ग. लंदन: ब्लूम्सबरी अकादमिक; 2011.
9. यूनेस्को. शिक्षा पर पुनर्विचार: वैश्विक साझा भलाई की ओर. पेरिस: यूनेस्को प्रकाशन; 2015.
10. विश्व बैंक. विश्व विकास रिपोर्ट: लैंगिक समानता और विकास. वाशिंगटन डीसी: विश्व बैंक; 2012.
11. भट्टाचार्य आर. क्या हम सशक्त हैं? भारतीय कार्यरत युवतियों के अनुभव. भारतीय लैंगिक अध्ययन पत्रिका. 2013;20(3):351–372.
12. द्रेज़े जे, सेन ए. अनिश्चित गौरव: भारत और उसकी अंतर्विरोधी वास्तविकताएँ. नई दिल्ली: पेंगुइन इंडिया; 2013.

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution **(CC BY 4.0)** license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.